सुप्रीम कोर्ट का फैसला

वैकल्पिक चिकित्सा चिकित्सकों के लिए कोई उत्पीड़न नहीं, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की नवीनतम सामग्री SLP (सिविल) क्रमांक 11262 / 24/11/2000 (निर्णय संख्या और क्रम संख्या 18/11/1998 में पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या205 / 92 में) कुछ स्पष्ट स्पष्टीकरण आदि के लिए दिल्ली सरकार & भारत के संघ (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील (SLP) भरी है, दिनांक १२ / ११ / १ ९९ on की सुनवाई १२ / ११ / को 2000। माननीय न्यायमूर्ति आरसी लाहोटी और माननीय न्यायमूर्ति शिवराज वी। पाटिल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। & भारत का संघ और अंतत: 24/11/2000 को माननीय अदालत की पीठ जिसमें न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू और बीएन अग्रवाल शामिल थे, ने मामले का मनोरंजन करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता (दिल्ली सरकार। और भारत संघ) द्वारा खारिज कर दिया गया। भारत की माननीय सर्वोच्च अदालत ने भी माननीय की यथास्थिति बनाए रखी ।

उच्च न्यायालय चेन्नई के निर्णय के अनुसार योजना आयोग की रिपोर्ट और सरकार का उत्तरार्ध। (No.110 / 8/4 / 77MPT / ME (पी) 1979 और नंबर 4-6 / 70 भारत सरकार के एमपीटी) आरएमपी प्रमाणपत्र धारक वैकल्पिक चिकित्सा में अभ्यास कर सकता है केवल वह सर्जरी, प्रसूति और विकिरण में अभ्यास नहीं कर सकता किसी भी रूप में चिकित्सा। वह किसी भी दवा को निर्धारित नहीं कर सकता है जिसमें किसी भी कीमत पर जी, एच एंड एल ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन नियम 1945 और अन्य खतरों की दवा शामिल हैं।

Iatros मेडिकल सोसाइटी द्वारा संचालित दवाओं की वैकल्पिक प्रणाली परिषद ने पूरे भारत में स्थापित चिकित्सा और पैरामेडिकल कॉलेज, विज्ञान और तकनीकी संस्थानों, अस्पताल, अनुसंधान केंद्र को चलाने और चलाने के साथ सम्मानित किया है।

साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के लिए वैकल्पिक चिकित्सा और पैरामेडिकल विज्ञान के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

कानूनी मैदान

चिकित्सा पद्धति के वैकल्पिक प्रणाली के क्षेत्र में कुछ कानूनी प्रसार और विभिन्न पाठ्यक्रम

कर्नाटक का उच्च स्तरीय सर्वेक्षण:

अपने अंतिम निर्णय में, सं। १६१ (२) १६ (२ ए) इत्यादि की संवैधानिक वैधता का उल्लेख करने के लिए याचिका संख्या १ /५३४-९ ६ / ९ ४ और ३६ ९ ६० / ९ ४ लिखी। दवाओं की किसी भी वैकल्पिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किसी भी क़ानून के तहत कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय:

इसके निर्णय दिनांक में कहा गया। CWP No. 4015/1996 और OM No.8468 / 1997 की 18/11/1998 जिसमें सरकार को भारत में वैकल्पिक चिकित्सा को नियमित करने और मान्यता देने के लिए उचित कार्रवाई करनी होगी।

CALCUTTA के माननीय उच्च न्यायालय:

CamScanner

अपने अंतिम निर्णय संविधान में न्यायिक अधिकार क्षेत्र 1988 की कोई 546 बात नहीं है। 07/05/1990 जिसे कलकत्ता लॉ जर्नल 1991 (2) सीएलजे पृष्ठ संख्या 173 से 187 में सूचित किया गया है, भारत में दवाओं की वैकल्पिक प्रणाली के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी वैधता के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

भारत का सबसे बड़ा सहारा:

चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली के एक मामले के अपने अंतिम निर्णय में कहा गया है कि "दिल्ली के उच्च न्यायालय के माननीय 'निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। भारत के आठ सप्ताह के भीतर "दवाओं की वैकल्पिक प्रणाली को नियमित करने के लिए।

भारत और दिल्ली सरकार के संघ दिल्ली उच्च न्यायालय CWP No. 4015/1996 दिनांक 18/11/1998 द्वारा अक्सर पूछे गए प्रश्न 205/92 में दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ एक SLP (सिविल) नं। 11262/2000। सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया है। दिनांक 24/11/2000

05-05-2010 इलेक्ट्रो होम्योपैथी नं। 5011/276/2009-एचआर दिनांक 5 वीं

02-05-2008 सुप्रीम कोर्ट ने इस अभ्यास को मान्यता दी। महाराष्ट्र निदेशालय स्वास्थ्य। मई 2010

23-04-2008 विजयनगरम अदि जुडी कोर्ट मजिस्ट्रेट ने BEMS प्रैक्टिस को मान्यता दी और इसे कानून में व्यवस्थित रखा।

22-12-2006 माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभ्यास को मान्यता दी।

10-01-2005 मेट्रोपॉलिटन सत्र अदालत, सेक-खराब मान्यता प्राप्त एमडी (ईएच) प्रैक्टिस और इलेक्ट्रो होम्योपैथी बोर्ड भी।

25-11-2003 केंद्रीय सरकार। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी।

14-02-2003 भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि, जिनके पास सामुदायिक चिकित्सा सेवा और ईडी सर्टिफिकेट (CMS) रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) हैं वे 42 ड्रग ग्रुप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एलोपैथी में जीवन रक्षक दवाओं की।

16-05-2001 माननीय मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय सेक-बैड ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभ्यास को मान्यता दी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि "भारत में किसी भी चिकित्सा परिषद, केंद्र को प्रैक्टिस में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

13।23-10-2000 XI मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, Sec-bad ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी और प्रासंगिक मेडिकल कॉलेज के अभ्यास को भी मान्यता दी।

आदेश द्वारा प्राप्त किया गया। भारत और एच एंड एफडब्ल्यू के मंत्रालय) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सं। V.25011 / 276/2009-HR Dated.05.05.2010 और C.30011 / 22/2010-HR दिनांकित दिनांक 26.06.2011।

काउंसिल द्वारा पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को योग्य चिकित्सकों के रूप में किसी भी प्रतिबंध के बिना, और किसी भी कानून द्वारा आवश्यक किसी अन्य प्रमाण पत्र की बीमारी, फिटनेस आदि जैसे चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उन्हें अधिकार देने के लिए अभ्यास करने का अधिकार देना। शिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों या कॉलेजों आदि की परीक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए संकाय की स्थापना करना; और उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि प्रदान करना।

CamScanner

यह तथ्य है कि तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने नैदानिक स्थापना अधिनियम लागू किया है। 2010. सभी राज्य केंद्रीय सरकार के आदेश को सम्मान और वजन दे रहे हैं। दिनांक 14/02/2011 इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा और अभ्यास के संबंध में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझाव और पारस्परिक परामर्श पर। भारत की। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 22/01/2015 को आदेश दिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सा अभ्यास पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत के 14/02/2011 को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम के तहत लागू नहीं है। इसके चिकित्सकों के क्लीनिक में पंजीकरण के लिए 2010 लेकिन सरकारी होम्योपैथ के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी या शिक्षा प्रदान करने का कोई अभ्यास नहीं है। आदेश V.25011 / 276/2009-एचआर दिनांक 05/05/2010

मद्रास उच्च न्यायालय ने भी 28/11/2016 को एक आदेश पारित किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार के अनुसार। भारत के आदेश क्रमांक V.25011 / 276/2009-HR दिनांक 05/05/2010 याचिकाकर्ता भारत में हर राज्य में बिना किसी बाधा के इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का सही अभ्यास कर सकता है। इसलिए, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों या तमिलनाडु के जिले के स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आदेश को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है क्योंकि यह आदेश राज्य सरकार द्वारा अप्राप्त है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इसलिए, राज्य सरकार। इसका सम्मान भी देना चाहिए।

राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी कानूनी और वैज्ञानिक विश्लेषण समिति सेटअप मान्यता है वनस्पति विज्ञानियों, फार्माकोलॉजिस्ट, नैदानिक अनुसंधान, इलेक्ट्रो होम्योपैथी विशेषज्ञ, अन्य चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञों से मिलकर। वरिष्ठ वैज्ञानिक -17, सीएमओ -40, कानूनी विशेषज्ञ -5 और राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपति सहित अन्य विशेषज्ञ।-16। प्राप्त और जांच किए गए सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर, समिति का एक स्पष्ट निर्णय है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सरल, किफायती, सुलभ और सुरक्षित चिकित्सीय दृष्टिकोण है, इसे राज्य में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता और खूबियों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने हालांकि विश्वास व्यक्त किया है और राज्य सरकार को आवश्यक कानून का मसौदा तैयार करने और राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उचित मान्यता देने के लिए वैधानिक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। अंततः 09/03/2018 को राजस्थान सरकार की विधानसभा। राजस्थान राज्य में इस प्रणाली को मान्यता देते हुए, 2018 की मेडिसिन बिल नंबर 13 की इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रणाली पारित कर दी गई है। माननीय सरकार। राजस्थान राज्य ने पहले ही 10 अक्टूबर, 2018 को विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसलिए, राजस्थान जैसे राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रणाली एक मान्यता प्राप्त प्रणाली है।

सरकार के बिना देश में इलेक्ट्रोहोमोपैथी की शिक्षा और अभ्यास जारी है। मान्यता

भले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा की प्रणाली के रूप में मान्यता नहीं है, देश में 2 लाख से अधिक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक इस प्रणाली का हिस्सा हैं और देश भर के 150 से अधिक कॉलेज इलेक्ट्रोपैथी में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, सीखा है। इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी का एक व्युत्पन्न है जो गैर-जहरीले पौधों के उपचार पर निर्भर करता है। देश भर में 150 से अधिक कॉलेज इलेक्ट्रोपैथी में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक व्यापक रूप से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीईएमएस) है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में स्वास्थ्य अधिवक्ता समूह चिकत्सांसर ट्रस्ट द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा की प्रणाली के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि मंत्रालय किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नैदानिक अभ्यास का समर्थन नहीं करता है क्योंकि संबंधित विधेयक अभी भी विचाराधीन है। भारतीय संसद का।

7/4 अप्रैल को दायर अपने आरटीआई आवेदन में, चिकत्सांसर ट्रस्ट ने कहा है कि किसी भी सरकारी विनियमन के अभाव में देश भर में व्यापक स्तर पर खलबली मची है।

CamScanner

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के मुद्दे पर, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के सामने आ चुका है, जबकि इसके चिकित्सकों का कहना है कि किसी भी कानून ने इसके अभ्यास पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और वे संविधान द्वारा गारंटी के अनुसार किसी पेशे में शामिल होने के हकदार हैं। इलेक्ट्रो होमियोपैथिक चिकित्सकों का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अच्छी तरह से संरक्षित है।

2 लाख से अधिक इलेक्ट्रोपैथ गैर-पंजीकृत तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि फीता में कोई अधिनियम नहीं है। इस तरह यह केंद्र या राज्य सरकार के चिकित्सा अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। इससे मरीज की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है क्योंकि देश के कई गांवों में इस पर कवायद चल रही है। इस प्रणाली की मान्यता 2005 से विधेयक के रूप में संसद में विचाराधीन है। " एक अधिसूचना के अनुसार 14015/25/96-यू एंड एच (आर) (पीटी), इलेक्ट्रो होम्योपैथिक व्यवसायी को अभ्यास करने की अनुमति नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 2008 में दायर एक रिट याचिका के माध्यम से अधिसूचना को चुनौती दी गई थी और फैसला यह था कि इलेक्ट्रोपैथी / इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अभ्यास भारत के किसी भी राज्य में निषिद्ध नहीं है।

आधुनिक चिकित्सा या किसी अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद / यूनानी चिकित्सा पद्धति के अभ्यास के लिए, मेडिकल काउंसिल अधिनियम के तहत पंजीकरण आवश्यक है। इन पंजीकरणों को प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निर्धारित योग्यताएं भी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा की एक पूरी तरह से अलग प्रणाली है। इसका अभ्यास भारत के किसी भी राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है। इसलिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अभ्यास के साथ आगे बढ़ने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद (19) (1) (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है। डॉक्टर भारत की सरकार द्वारा तय कानून से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि कानून भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को घोषित किया है। 2003 कि जो लोग सामुदायिक चिकित्सा सेवा प्रमाणपत्र (CMS) या ग्रामीण चिकित्सा व्यवसायी (RMP) कर रहे हैं, वे एलोपैथ में जीवन रक्षक दवाओं के 42 दवा समूहों पर अभ्यास कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय सिकंदराबाद ने 16 मई 2001 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस को मान्यता दी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि "भारत में किसी भी परिषद को प्रैक्टिस में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।" मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सिकंदराबाद ने 23 अक्टूबर, 2000 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रथा को मान्यता दी थी।

7 मई, 1999 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी। जबलपुर के उच्च न्यायालय ने 19 मार्च, 1999 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभ्यास को मान्यता दी। 9/1998 को मद्रास उच्च न्यायालय ने डॉक्टर नाम का इस्तेमाल करने से संबंधित निर्णय दिया था। "जो लोग चिकित्सा की होम्योपैथी प्रणाली का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें" ईएच "(इलेक्ट्रो होमियोपैथिक) के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करके नाम से पहले" डॉक्टर "शब्द का उपयोग करने का अधिकार है।

CamScanner

Compilation of Court Decisions / Orders in favour of Electro■Homoeopathy (In

Generated on: 2025-12-01

Rajesh Kumar v. Union of India (Order) - Allahabad High Court

Court: Allahabad High Court
Order/File: Order dated 16-05-2024
Date / Citation: Rajesh Kumar v. Union of India, Order dated 16-05-2024
Held that petitioners can practice Electro Homeopathy so long as it is not banned; cannot use prefix 'Doctor'. Order dat ed 16 May 2024.
Source / Link (for full judgment PDF or report): https://www.scconline.com/blog/post/2024/05/22/allahabad-high-court-allowed-practice-electro-home

CRR No. 2597/2022 - High Court of Madhya Pradesh (Indore Bench)

Court: High Court of Madhya Pradesh
Order/File: Final Order dated 24-08-2023
Date / Citation: CRR No.2597/2022, Order dated 24-08-2023
Petitioner entitled to practice Electro Homeopathic System of Medicine under respective council; order dated 24 Aug 2023 .
Source / Link (for full judgment PDF or report): MP High Court PDF: CRR_2597_2022_FinalOrder_24-Aug-2023 (mphc.gov.in)

C.W.P. No. 7893/2002 - Punjab & Haryana High Court

Court: Punjab & Haryana High Court (Chandigarh)
Order/File: Order dated 10-08-2009
Date / Citation: C.W.P. No.7893/2002, Order dated 10-08-2009
Discussion on right to practice; court observed regulatory concerns and issues regarding qualifications under Medical Co uncil Act. Order dated 10 Aug 2009.
Source / Link (for full judgment PDF or report): High Court Chandigarh PDF (highcourtchd.gov.in)

Government of India Order regarding Electro Homoeopathy

Court: Government of India, Ministry of Health & Family Welfare (notification)
Order/File: Order dated 05-05-2010
Date / Citation: GOI Order No. (see PDF), dated 05-05-2010
Government communication regarding recognition/consideration of Electro Homoeopathy and directions to states. File PDF a vailable.
Source / Link (for full judgment PDF or report): GOI order dated 05-05-2010 (indiaelectropathy.org / Government PDF)

Supreme Court reference mentioning Electro Homeopathy (order)

Court: Supreme Court of India
Order/File: Order dated 22-01-2015 (reported by stakeholders)
Date / Citation: Supreme Court order (reported) dated 22-01-2015
Reported order noting there is no ban on practice of Electro Homoeopathy (as per secondary sources).
Source / Link (for full judgment PDF or report): Reported on caamsc.in / casmind pages

Notes: This compilation includes publicly available orders and secondary reports. For full judgment texts, consult the source links provided.